यूपी सरकार भी बनाएगी अपना डाटा सेंटर, 51 करोड़ रुपये जारी

■ विनोद पांडेय

लखनऊ। राज्य सरकार भी 6 मेगावाट क्षमता का अपना डाटा सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। आईटी इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने तीन स्थानों पर भूमि देखी है। इनमें से नादरगंज स्थित आईटी इलेक्ट्रानिक्स विभाग की भूमि उपयुक्त मानी जा रही है। जल्दी ही भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है।

मौजूदा दौर में डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इससे ज्यादा डाटा की सुरक्षा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अपना डाटा सेंटर बनाने जा रही है। अभी योजना भवन में एक एमबीए का डाटा सेंटर काम कर रहा है लेकिन इसकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार की लगभग सभी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं। इस समय विभागों की वेबसाइट के दो दर्जन से अधिक पोर्टल चल रहे हैं। भर्ती आयोगों के डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता है। इस नाते भी मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।

> उच्च तकनीकी क्षमता का नया डाटा सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए तीन स्थानों पर जमीन देखी गई है। नादरगंज में विभाग की भी भूमि खाली है। इसके एक हिस्से में डाटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आर्किटेक्ट कंपनी का चयन कर लिया गया है।
>
> **-आलोक कुमार,** प्रमुख सचिव
> आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रदेश में इन दिनों टेरा बाइट, पेंट बाइट में डाटा जेनरेट हो रहा है। डाटा की सुरक्षा, स्टोरेज और बढ़ती मांग को देखते हुए स्टेट डाटा सेंटर की जरूरत महसूस की जा रही है। मौजूदा डाटा सेंटर की क्षमता एक मेगावाट तक ही है और इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता।

बढ़ती डिजिटल सेवाओं और डाटा जेनरेशन की स्थिति को देखते हुए दूसरे डाटा सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नए डाटा सेंटर की क्षमता 6 मेगावाट तक होगी।